www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 134 | जौनपुर सोमवार, 29 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

विधानसभा चुनाव में 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

असम, एजेंसी। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएंगी। राज्य विधानसभा में कुल 126 सीट हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एआईयूडीएफ के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। गोगोई ने उसे श्सांप्रदायिकश पार्टी बताया। कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर एक बैठक को संबोधित करते हुए गोगोई ने कहा कि जनविरोधी भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस 2026 के असम विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में एआईयूडीएफ जैसी सांप्रदायिक पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस राज्य की 126 सीटों में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी विधानसभा क्षेत्रों को आपसी बातचीत से गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व में असम के लोगों से छीनी गई गरिमा को वापस दिलाया जाएगा।

नेहरू के पत्र और दस्तावेज पीएम संग्रहालय को लौटाएं – सोनिया गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े पत्र और दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) को वापस लौटाएं। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज किसी एक परिवार या व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे देश की विरासत हैं। पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना नेहरू जी के निधन के बाद हुई थी। पहले इसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) कहा जाता था, जिसे 2023 में बदलकर पीएमएमएल कर दिया गया। इस संग्रहालय में सभी पीएम से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं।

पीएमएमएल में कुल करीब 2.5 करोड़ दस्तावेज

उन्होंने कहा कि 1970 से 1990 के बीच नेहरू जी से जुड़े गैर–सरकारी दस्तावेज, निजी पत्र, उन्हें मिले जवाब और उनकी निजी टिप्पणियां संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थीं। पीएमएमएल में कुल करीब 2.5 करोड़ दस्तावेज हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख दस्तावेज केवल पंडित नेहरू से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि एम. वी. राजन ने पत्र लिखकर नेहरू जी के निजी पारिवारिक पत्र और नोट्स वापस मांगे थे।

आतंक के खिलाफ सभी राज्यों में होगा एक जैसा आतंकवाद-विरोधी दस्ता

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति को दोहराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को एक समान आतंकवाद विरोधी ढांचा शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के नवगठित ट्रैक 2 में डिजिटल उपकरणों के डेटा, बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल गुमनामी को उजागर करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में जांच के दौरान सीखे गए सबक, आतंकी मॉड्यूल को पहले से ही निष्क्रिय करने के उपाय, उग्रवादी उग्रवाद, पूर्वोत्तर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सीखे गए सबक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विभिन्न हाइब्रिड खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का पांचवां आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, शनिवार को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आतंकवाद– विरोधी क्षमता को बढ़ाने के मकसद से एक आदर्श एटीएस संरचना तैयार करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के बीच समन्वय और निर्बाध वास्तविक समय सूचना आदान–प्रदान को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के किसी भी रूप के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को दोहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के आतंकवाद–विरोधी तंत्र को

मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गृह मंत्री ने राज्यों को भारत की आतंकवाद–विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एकसमान आतंकवाद–विरोधी दस्ते (एटीएस) संरचना को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पूरे देश में एक मजबूत, एकसमान और सुसंगत परिचालन क्षमता के बिना हम खुफिया जानकारी का उचित उपयोग और प्रभावी समन्वित जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर सकते।

हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी कृत्य की योजना बनाने वालों को सजा दी

गृह मंत्री ने पहलगाम और दिल्ली के लाल किले पर हुए दो आतंकी हमलों में विभिन्न एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों की सफल कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहलगाम लक्षित हमले के मामले में इन एजेंसियों की गहन कार्रवाई ने देश को गौरवान्वित किया है। इस जघन्य हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को सफलतापूर्वक ट्रैक करके मार गिराने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह पहली आतंकी घटना है जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी कृत्य की योजना बनाने वालों को सजा दी है। ऑपरेशन महादेव के जरिए हमले को में शामिल आतंकवादियों को खत्म किया गया है। लगातार बदलती प्रौद्योगिकी और आतंकी परिदृश्य की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री ने इसकी निरंतर जांच और पुनर्मूल्यांकन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने केंद्र और राज्यों की सभी एजेंसियों से साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध के प्रति सतर्कता, बहु–सुरक्षा स्तर और खुफिया जानकारी के निर्बाध प्रवाह जैसे अंतरराष्ट्रीय आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। अपनी जांच और अभियोजन क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करते हुए शाह ने राज्यों से अपने सुरक्षा और पुलिस कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने का आग्रह किया। शनिवार शाम को समापन भाषण में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आतंकवाद के किसी भी रूप के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को रेखांकित करने का एक साधन बताया है। चाहे वह सीमा पार आतंकवाद हो, मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद हो या साइबर आतंकवाद। उन्होंने देश के सामने मौजूद विभिन्न खतरों, विशेष रूप से कट्टरता, भर्ती और कमजोर युवाओं के शोषण से उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह सचिव ने कहा कि आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के नवगठित ट्रैक 2 में डिजिटल डिवाइस डेटा और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल गुमनामी को उजागर करना। उन्होंने एनआईए द्वारा हासिल की गई 90% से अधिक की उच्च दोषसिद्धि दर की सराहना की।

207 सीटों पर बनी भाजपा–शिवसेना के बीच सहमति

मुंबई, एजेंसी। भाजपा के शहर प्रमुख अमित साटम ने कहा कि सत्ताधारी महायुति के बीच मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए 227 में से 207 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें बीजेपी 128 और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी और अन्य निकाय चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। महायुति में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है।

20 सीटों पर उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर फैसला किया जाएगा

साटम ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, बीएमसी की 207 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें से बीजेपी 128 और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 20 सीटों पर बातचीत चल रही है। इन सीटों पर उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। साटम ने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है। मायने यह रखता है कि कौन मुंबईकरों को भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक प्रशासन दे सकता है। यह हिंदुत्व गठबंधन मुंबई को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए है। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों से तुलना करते हुए साटम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, जबकि शिंदे के कुछ नेताओं ने कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था।

अभी क्या है बीएमसी की स्थिति

महायुति का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन से है। बीएमसी में 227 सीटें हैं और कुल 1,03,44,315 मतदाता हैं, जिनमें 55,16,707 पुरुष, 48,26,509 महिलाएं और 1,099 मतदाता अन्य के रूप में पंजीकृत हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने की नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर की यात्रा, नौसैनिकों की सराहना किया

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना की स्वदेशी अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर में यात्रा की। राष्ट्रपति मुर्मू पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले फरवरी 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आईएनएस सिंधु रक्षक में पनडुब्बी यात्रा की थी। अधिकारियों के मुताबिक, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे से कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में हुई इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के साथ थे। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं। नौसैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति मुर्मू ने पनडुब्बी में प्रवेश करने से पहले वहां मौजूद नौसैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने आईएनएस वाघशीर के चालक दल

से बातचीत की और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने इस स्वदेशी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना की पेशेवर उत्कृष्टता और युद्ध तैयारी का बेहतरीन उदाहरण बताया। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वाघशीर के भीतर जाकर समुद्र के नीचे यात्रा की। सचिवालय ने बताया कि राष्ट्रपति को भारत की समुद्री रणनीति में पनडुब्बी बेड़े की भूमिका, उसकी परिचालन क्षमताओं और राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा में उसके योगदान के बारे में जानकारी दी गई। आईएनएस वाघशीर के चालक दल से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और निस्वार्थ सेवा भावना की सराहना की।

सचिवालय ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति ने बताया कि यह स्वदेशी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता, युद्ध तत्परता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आईएनएस वाघशीर पी75 स्कॉर्पीन परियोजना के तहत बनी छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जिसे जनवरी में नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना अधिकारियों के अनुसार, यह दुनिया की सबसे शांत और उपयोगी डीजल–इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है।

श्रीहरिकोटा में तीसरा लान्च पैड विकसित करेगा इसरो, प्रक्षेपण अभियानों में आएगी तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र पर तीसरा प्रक्षेपण पैड विकसित करने की प्रक्रिया में है और वर्तमान में इसके लिए उपयुक्त कंपनियों की तलाश की जा रही है। यह जानकारी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक पद्मकुमार ईएस ने रविवार को दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर पूर्व में स्थित श्रीहरिकोटा परिसर 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बंगलूरू स्थित अंतरिक्ष एजेंसी को विभिन्न प्रक्षेपण यानों के जरिये उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाने की सेवा मुहैया कराता रहा है।

पद्मकुमार ईएस ने कहा कि अंतरिक्ष में विभिन्न कक्षाओं में 12,000–14,000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बड़े उपग्रहों को स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ने के लिए इसरो को बड़े प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसरो तीसरे प्रक्षेपण पैड की योजना बना रहा है। हमारी योजना चार साल में तीसरा 'लॉन्च पैड' स्थापित कर संचालित करने की है। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, हम खरीद प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और इस विशाल परियोजना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त कंपनियों की पहचान कर रहे हैं। पद्मकुमार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एक बार तीसरा प्रक्षेपण पैड चालू हो जाने के बाद, इसका उपयोग 14,000 किलोग्राम से अधिक वजन के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा, जिन्हें अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों (एनजीएलवी) द्वारा कक्षा में ले जाया जाएगा। तूतीकोरिन में निर्माणाधीन इसरो प्रक्षेपण परिसर के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस सुविधा का उपयोग लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों (एसएसएलवी) को प्रक्षेपण करने के लिए किया जाएगा, जो उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। इन उपग्रहों का वजन लगभग 500 किलोग्राम हो सकता है और इन्हें निम्न–स्तरीय विद्युत क्षेत्र (एलईओ) में स्थापित किया जा सकता है। ऐसे मिशनों के लिए, हम उस सुविधा का उपयोग करेंगे।

भारत ने हाल में रचा था कीर्तिमान

इसरो ने 24 दिसंबर को लगभग 6,000 किलोग्राम वजनी अमेरिकी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक–2 को एलवीएम3–एम6 रॉकेट के जरिये पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया था। इसके साथ ही अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार भारतीय धरती से इतने अधिक वजन का उपग्रह कक्षा में भेजा था।

दिल्ली के विकास के लिए 1000 करोड़ की योजनाएं पास, व्यापारियों को लौटाए 915 करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के बने हुए एक वर्ष भी नहीं बीता है, लेकिन इसी बीच सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं पास कर चुकी है। यह राशि सड़कों को ठीक करने से लेकर गलियों–कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट ठीक करने से लेकर विभिन्न योजनाओं में खर्च की गई हैं। सरकार ने इसे जनता के हितों के लिए उठाया गया बड़ा कदम बताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार में सुगमता) को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए व्यापारियों को लाइसेंसिंग व्यवस्था में बड़ी राहत दी गई है। किसी काम के लिए अब उन्हें महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि चंद दिनों में सिंगल विंडो सिस्टम से उन्हें हर तरह की क्लीयरेंस दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है क्योंकि उद्यमी केवल व्यापार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर देश के विकास में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

व्यापारियों के लिए सरकार ने पहला ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से उद्योग और व्यापार जगत की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने का समय 120 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। सरकार ने सस्ता कर्ज देकर व्यापारियों को बढ़ावा देने का काम किया है।

इंडिगो संकट के बाद उड्डयन मंत्रालय सतर्क

नई दिल्ली, एजेंसी। हवाई यात्रियों की शिकायतों का तेजी से समाधान करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम (पीएसीआर) की शुरुआत की है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे, सातों दिन काम कर रहा है और यात्रियों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई कर रहा है।

10 दिसंबर से शुरू किया गया था पीएसीआर

पीएसीआर को 10 दिसंबर से शुरू किया गया था। यह कदम हाल ही में इंडिगो की परिचालन समस्याओं, कोहरे और अन्य कारणों से हुई उड़ान रद्द होने व देरी की घटनाओं के बाद उठाया गया। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि कंट्रोल रूम के शुरू होने से शिकायत निवारण में साफ सुधार हुआ है और यात्रियों व अन्य संबंधित पक्षों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। मंत्रालय के अनुसार, एयरसेवा, सोशल मीडिया और कॉल के जरिए आने वाली शिकायतों को अब पीएसीआर के माध्यम से तेजी से सुलझाया जा रहा है।

अब तक 13000 से अधिक शिकायतों का समाधान

समीर सिन्हा ने बताया कि अब तक 13000 से अधिक यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इनमें उड़ान रद्द होने, टिकट रिफंड, खोया हुआ सामान और विमान में भोजन न मिलने जैसी समस्याएं शामिल हैं। सभी मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि समाधान में देरी न हो। कई एयरलाइंस के प्रतिनिधियों ने बताया कि यात्रियों की शिकायतें अलग–अलग तरह की होती हैं, लेकिन अधिकतर मामलों को 72 घंटे के भीतर सुलझाने की कोशिश की जाती है। इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर के अधिकारियों ने माना कि कंट्रोल रूम के कारण कामकाज सुचारू हुआ है और यात्रियों को राहत मिल रही है।

अरावली विवाद पर सुप्रीम सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देश में चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच इस अहम पर्यावरणीय मुद्दे पर विचार करेगी, जिससे अरावली के संरक्षण और खनन नीति की दिशा तय हो सकती है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की एक एक समान परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के आधार पर

लिया।

पहले समझिए क्या है अरावली की नई परिभाषा?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर समिति की सिफारिशों के अनुसार, अरावली पहाड़ी वह भूमि होगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक हो, जबकि अगर दो या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के भीतर हों तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। इस परिभाषा में पहाड़ियों के साथ उनकी ढलान, आसपास की जमीन और जुड़े भू–आकार भी शामिल होंगे।

जयराम रमेश ने सरकार पर उठाए सवाल

इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नई परिभाषा से अरावली पहाड़ियों का बंटवारा होगा और उनकी भौगोलिक व पर्यावरणीय पहचान कमजोर हो जाएगी।

जयराम रमेश ने पूछे चार बड़े सवाल

जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री से चार बड़े सवाल पूछे है। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि 2012 से राजस्थान में अरावली की परिभाषा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के आधार पर तय थी, जिसमें 3 डिग्री या ज्यादा ढलान वाले इलाके भी पहाड़ी माने जाते थे?

संपादकीय

नए साल में और सता सकती है गर्मी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल धरती का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन धरती को लगातार गर्म कर रहा है और चरम मौसमी घटनाएं बढ़ा रहा है। ब्रिटेन के मौसम विभाग का अनुमान है कि 2024 की तुलना में 2026 थोड़ा ठंडा जरूर रहेगा, फिर भी 2026 के, 1850 के बाद से दर्ज चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने की आशंका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2026 में तापमान 1850–1900 की तुलना में 1.34 से 1.58 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो सकता है।

इस पूर्वानुमान का नेतृत्व करने वाले मौसम विभाग के जलवायु वैज्ञानिक एडम स्केफ ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में वैश्विक तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है, और आशंका है कि 2026 लगातार चौथा साल होगा, जब ऐसा होगा। इससे पहले, वैश्विक तापमान कभी 1.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं था।

लगभग 10 साल पहले पेरिस जलवायु बैठक में दुनिया के नेताओं ने वादा किया था कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाएगा। इस लक्ष्य को पाना अब भी वैज्ञानिक रूप से मुमकिन है।

मौसम विभाग के जलवायु वैज्ञानिक निक डंस्टन ने कहा कि 2024 में पहली बार तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देखने को मिला, और 2026 में ऐसा दोबारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि हम अब पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच रहे हैं।

यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने बताया कि 2025 रिकॉर्ड के अनुसार, दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल हो सकता है, और यह विश्व मौसम संगठन के अनुमानों की भी पुष्टि करता है। अल नीनो जैसी गर्म प्राकृतिक स्थितियों ने 2023 और 2024 में तापमान बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि 2025 में कमजोर ला नीना के कारण यह बढ़ोतरी थोड़ी कम रही। बिजलीघरों, गाड़ियों और बॉयलरों से निकलने वाली गैसें धरती को गर्म कर रही हैं, और जंगलों के नष्ट होने से हवा से कार्बन सोखने की प्राकृतिक क्षमता भी घट रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले साल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। विशेषज्ञों को यह चिंता भी है कि धरती के प्राकृतिक कार्बन सिंक, यानी वे हिस्से जो हवा से कार्बन सोखते हैं, भविष्य में ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं।

बदलती वैश्विक जनसांख्यिकी की दिशा

अरुण कुमार

भारत आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और लगभग 1.45 अरब की आबादी के साथ उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ती जीवन प्रत्याशा इसकी प्रमुख वजह रही हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव, सीमित रोजगार, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और संसाधनों की कमी

जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। मानव इतिहास में जनसंख्या हमेशा चुनौतियों और अवसरों दोनों की धुरी रही है। आज जब दुनिया की आबादी 8 अरब के पार पहुंच चुकी है, तब वैश्विक जनसांख्यिकी पहले से कहीं अधिक जटिल और परिवर्तनशील हो गई है। तकनीकी प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं ने इस बदलाव को नई दिशा दी है। 2025 की जनसंख्या रैंकिंग इसी परिवर्तन का संकेत है, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख देश बनकर उभरे हैं।

भारत आज दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और लगभग 1.45 अरब की आबादी के साथ उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बढ़ती जीवन प्रत्याशा इसकी प्रमुख वजह रही हैं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ शहरों पर दबाव, सीमित रोजगार, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। इसके बावजूद भारत की विशाल युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो सही नीतियों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकती है। साथ ही, देश की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 पर आना एक महत्वपूर्ण बदलाव हैकृकम बच्चों के कारण महिलाओं के पास शिक्षा, कौशल और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के अधिक अवसर होंगे, जिससे उत्पादनशीलता और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

चीन, जिसने दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने का गौरव रखा, आज जनसंख्या वृद्धि की उलटी दिशा में बढ़ रहा है। लगभग 1.42 अरब की आबादी के बावजूद वहां जन्म दर तेजी से गिर रही है। 1979 से 2015 तक लागू रही एक–बच्चा नीति के कारण आज चीन असंतुलित आयु संरचना, तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि सरकार अब परिवार विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है, पर सामाजिक–आर्थिक बदलावों ने छोटे परिवार की प्रवृत्ति को मजबूत कर दिया है। इसका सीधा असर चीन की विशाल श्रम शक्ति और उसके विनिर्माण–केंद्रित आर्थिक मॉडल पर पड़ने वाला है।

अमेरिका लगभग 33.5 करोड़ की आबादी के साथ जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसकी जनसांख्यिकीय विविधता और जनसंख्या वृद्धि का मुख्य आधार जन्म दर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन है। यही प्रवासन तकनीक, शिक्षा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उसकी आर्थिक गतिशीलता को मजबूती देता है। हालांकि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में आव्रजन नीतियों में होने वाले बदलाव भविष्य की अमेरिकी जनसंख्या संरचना को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं।

इंडोनेशिया, लगभग 27.5 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हजारों द्वीपों में फैले इस देश में जावा जैसे अत्यंत घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार से जन्म दर में कमी आई है, फिर भी विशाल युवा आबादी के कारण रोजगार और बुनियादी ढांचे पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान, 24 करोड़ से अधिक आबादी के साथ पांचवें स्थान पर है और यहां दुनिया की सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दरों में से एक है। अत्यधिक युवा आबादी विकास की संभावना भी है और बड़ी चुनौती भी। तेज शहरीकरण के कारण जल, ऊर्जा, आवास और रोजगार जैसी समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। दुनिया की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करने वाले कई कारक समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं। जन्म दर में अंतर, आर्थिक अवसर, सामाजिक प्रवृत्तियां, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और लंबे समय तक लागू रहने वाली सरकारी नीतियां इन कारकों का हिस्सा हैं।प्रवासन आज आधुनिक दुनिया की जनसंख्या को आकार देने वाली एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। बेहतर शिक्षा, सुरक्षित जीवन, आर्थिक अवसर और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विस्थापन ने इसे वैश्विक प्रक्रिया में बदल दिया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अनेक यूरोपीय देश अपनी जनसंख्या और श्रम शक्ति को संतुलित रखने के लिए प्रवासन पर निर्भर हैं, जबकि आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों से युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है।

सिर्फ नारा नहीं था नरेगा के तहत काम का अधिकार

डॉ.अजीत

संसदीय स्थायी समिति के संदर्भ के बिना और राज्यों, श्रमिक संगठनों या नागरिक समाज के साथ गंभीर परामर्श किए बिना वीबी–जी राम जी विधेयक को जिस तरह से पेश तथा पारित किया गया है, वह भी उतना ही आपत्तिजनक है। एक ऐसा कानून, जो नागरिक और राज्य के बीच संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है,उसके लिए यह प्रक्रियागत जल्दबाजी लोक तांत्रिक मानदंडों में फिट नहीं बैठती है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 (वीबी–जी राम जी विधेयक)श का पारित होना भारत के सबसे परिणामदायी सामाजिक कानूनों में से एक के निर्णायक विराम का प्रतीक है। इसने 2005 के ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का स्थान लिया जिसे बाद में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। सरकार इस बात पर जोर देती है कि नया कानून एक ऐसा सुधार है जो गारंटीकृत कार्य की सीमा को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है लेकिन यह दावा सरसरी तौर से भी खरा नहीं उतरता है। नया विधेयक वास्तव में कहीं अधिक परेशान करने वाला है– यह काम करने के न्यायोचित अधिकार को समाप्त करता है, नियंत्रण को पुर्नकेन्द्रीकृत करता है, राजकोषीय बोझ को राज्यों को स्थानांतरित करता है और ग्रामीण भारत में श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करता है। नरेगा कभी भी सिर्फ एक कल्याणकारी योजना नहीं थी। यह संविधान के अनुच्छेद 41– काम करने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए राज्य के दायित्व– को लागू करने योग्य पात्रता में बदलने वाला एक कानूनी नवाचार था। यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता था तो राज्य कानूनी रूप से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए बाध्य था। नरेगा के तहत रोजगार– मांग–आधारित, सार्वभौमिक था और यह अधिकार न्यायोचित था। वीबी–जी राम जी विधेयक इस अधिकार– आधारित, मांग आधारित ढांचे को आपूर्ति–संचालित, बजट–कैप्ड योजना के साथ प्रतिस्थापित करता है जो सशर्त है तथा जिसकी गारंटी केंद्रीय आवंटन और प्रशासनिक विवेक पर है। याद रखने वाली बात यह है कि नरेगा की जड़ें महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना (ईजीएस) में थीं। 1970 के दशक की शुरुआत में पड़े विनाशकारी सूखे का मुकाबला करने के लिए बनाए गये ईजीएस को शहरी श्रमिकों को समर्पित कर वित्तपोषित और ग्रामीण रोजगार की वैधानिक गारंटी द्वारा समर्थित किया गया था। इसकी विशेषता इसकी सरलता में निहित है– मांग पर काम, स्थानीय रूप से निर्धारित सार्वजनिक कार्य और मजदूरी का भुगतान श्रमिक के अधिकार के रूप में होना। यह नरेगा के लिए बौद्धिक और संस्थागत टेम्पलेट बन गया। ईजीएस का डिजाइन गांधीवादी नेता वीएस पागे के नेतृत्व में लागू की गई पायलट परियोजनाओं से प्रेरित था। ईजीएस ने एक राजनीतिक सच्चाई का भी खुलासा किया जो आज भी प्रासंगिक है। इसने मजदूरी के लिए एक धरातल निर्धारित करके तथा श्रमिकों को बाहर निकलने का विकल्प देकर श्रमिकों की जमींदारों और ठेकेदारों पर निर्भरता को कम कर दिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे जमींदार अभिजात वर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिन्होंने श्श्रम की कमीश और बढ़ती मजदूरी के बारे में शिकायत की। नए विधेयक का प्रावधान कृषि मौसमों के चरम के दौरान रोजगार में 60 दिनों के ठहराव की अनुमति देता है जो जाहिरा तौर पर श्रम उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए तटस्थ नीति डिजाइन की तरह कम और उन लोगों की सुविधा के लिए रियायत की तरह अधिक है जो लंबे समय से नरेगा के ग्रामीण श्रम बाजारों पर प्रभाव से नाराज हैं। सरकार के बचाव का केंद्र बिंदु गारंटीकृत रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है लेकिन यह काफी हद तक प्रतीकात्मक है। यहां तक कि नरेगा के तहत भी अधिकांश वर्षों में वास्तव में परिवारों के एक छोटे से हिस्से को ही पूरे 100 दिनों का काम मिलता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नया विधेयक केंद्र द्वारा निर्धारित श्राज्यवार मानक आवंटनश के माध्यम से कुल व्यय को सीमित करता है। इस सीमा से अधिक का कोई भी खर्च केंद्र द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राज्यों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। कानून में बजट कैप को शामिल कर यह विधेयक एक कानूनी गारंटी को केंद्रीय राशन कार्यक्रम में परिवर्तित करता है। अपनी तमाम कमियों के बावजूद नरेगा ने सहकारी संघवाद के व्यावहारिक रूप को मूर्त रूप दिया था। केंद्र ने यह मानते हुए कि उच्च बेरोजगारी वाले गरीब राज्यों में भी कमजोर राजकोषीय क्षमता है, पूरी मजदूरी लागत तथा अधिकांश सामग्री लागत को वहन किया। वीबी–जी राम जी विधेयक इस तर्क को पलट देता है। प्रस्तावित 60:40 लागत–साझे का पैटर्न राज्यों पर अनुमानतरू सालाना 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा अतिरिक्त बोझ डालता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब जीएसटी और उधार लेने की बाधाओं के कारण राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता पहले ही खत्म हो चुकी है। यह केवल एक राजकोषीय मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक संवैधानिक मुद्दा भी है। रोजगार और लोक निर्माण पूरी तरह से राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं तथा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नया विधेयक इस बात का उदाहरण है कि विशेषज्ञों ने इसे केंद्र की सातवीं अनुसूची में चोरी छिपे घुसना कहा है– संवैधानिक रूप से राज्यों को सौंपे गए विषयों पर केंद्रीय नियंत्रण का विस्तार करना जबकि राज्यों को कार्यान्वयन की वित्तीय और राजनीतिक लागतों को वहन करने के लिए छोड़ देता है।

.... विविध/स्वास्थ्य ....

दिल्ली में रहते हैं तो 1 जनवरी पर कहां जाएं, कैसे मनाएं नए साल का जश्न

अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नया साल केवल घर में बैठकर मनाना बोरिंग हो सकता है। राजधानी में कई ऐसी जगहें हैं, जहां जाकर आप नए साल की रात को खास और यादगार बना सकते हैं। चाहे आप शॉपिंग के शौकीन हों, फाइन डाइनिंग पसंद करते हों या फिर लाइव म्यूजिक और पार्टी का मजा लेना चाहते हों, दिल्ली हर तरह के सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। दिल्ली में कई आउटडोर हॉटस्पॉट्स और बोटिंग या लाइट शो जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं तो आपके नए साल को और भी शानदार बना सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में नए साल पर कहां–कहां जाकर आप अपनी रात को खास बना सकते हैं। अगर साल का पहला दिन खास बनाएंगे तो आपका पूरा साल अच्छा रहेगा।

कनॉट प्लेस

कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे लोकप्रिय न्यू ईयर हॉटस्पॉट है। नए साल के मौके पर यहां की गलियां रोशनी और डेकोरेशन से जगमगा उठती हैं। नए साल के मौके पर कई रेस्टोरेंट्स और बार स्पेशल पार्टियों का आयोजन करते हैं। लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और स्पेशल ड्रिंक ऑफर के साथ, ये जगह दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट है।

हौज खास विलेज

हौज खास विलेज अपने कैफे, बार और लाइव म्यूजिक के लिए मशहूर है।

न्यू ईयर पर यहां लाइव बैंड परफॉर्मेंस और ओपन एयर पार्टी का मजा लिया जा सकता है। कूल एंबियंस और लेकसाइड वॉक इसे रोमांटिक और मजेदार दोनों बनाते हैं। ये जगह फूड और म्यूजिक के शौकीनों के लिए बेस्ट है।

दिल्ली हाट

अगर आप शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, तो किंग्सवे कैंप और दिल्ली हाट जाएं। यहां कलरफुल स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल फूड का मजा लिया जा सकता है। न्यू ईयर स्पेशल मार्केट और लाइव पर्फॉर्मेंस इसे और भी उत्सवपूर्ण बनाते हैं।

इंडिया गेट और राज घाट

इंडिया गेट और राज घाट पर न्यू ईयर वॉक और लाइट शो का आनंद लिया जा सकता है। इंडिया गेट के पास शाम के समय लाइटिंग और फैमिली गेट–टुगेदर का अनुभव बहुत खूबसूरत होता है। राज घाट का शांत वातावरण न्यू ईयर पर मेडिटेशन और वॉक के लिए परफेक्ट है।

बोटिंग करने जा सकते हैं

अगर आप थोड़ा एडवेंचर और रोमांटिक टच चाहते हैं, तो यमुना नदी या रिजॉर्ट एरिया में न्यू ईयर स्पेशल बोटिंग ट्रिप चुन सकते हैं।

पानी पर रात की लाइटिंग और ठंडी हवा का मजा सेलिब्रेशन को यादगार बना देता है।

घर पर ऐसे बनाएं बटर नान कि परिवारवाले भूल जाएं रेस्तरां वाला स्वाद

ढाबे और रेस्टोरेंट पर मिलने वाली नान का स्वाद इतना अच्छा होता है कि हर कोई उसे पसंद करता है। इसे हर तरह की पनीर की सब्जी और दाल मखनी के साथ कमाल का लगता है। पर, हर दिन बाजार में मिलने वाली नान को खाना संभव नहीं है।

ऐसे में आप चाहें तो इसे घर पर बना सकती हैं। तो अगर आप घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल बटर नान बनाना चाहते हैं, तो ये लेख आपके लिए बिल्कुल सही है। घर पर बाजार जैसी नान बनाने के लिए आपको बस सही सामग्री, थोड़ी मेहनत और सही विधि की जरूरत है।

हम आपको नान बनाने का सही तरीका बताएंगे, ताकि इसे बनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए घर पर ही पार्टी स्टाइल बटर नान बना सकते हैं। इसे खाने का मजा रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा और आप अपनी कुकिंग स्किल्स भी दिखा पाएंगे।

ये है सामग्री

नान बनाने के लिए आपको मैदा, दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, चीनी, तेलध्घी और मक्खन की जरूरत पड़ेगी।

ये है विधि

बटर नान बनाने के लिए सबसे पहले सारी सामग्री तैयार कर लें। ये सभी सामग्री आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं और इन्हें मिलाकर ही नान का मुलायम और फूला हुआ टेक्सचर आता है। सभी सामान को एक साथ लेने के बाद आटा गूंथने की प्रक्रिया शुरू करें।

एक बड़े बाउल में मैदा डालें और उसमें दही, नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाएं। इसे हाथों या मिक्सर की मदद से अच्छी तरह गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत ढीला। गूंथे हुए आटे को नरम होना चाहिए। अब आटे को ढककर लगभग 1–2 घंटे के लिए रख दें, ताकि ये हल्का फुल जाए।

ये प्रोसेस नान को मुलायम बनाने में मदद करता है और जब आप इसे सेकेंगे तो ये आसानी से फूलेगा। फूला हुआ आटा तैयार होने के बाद छोटी–छोटी लोइयां बनाएं और बेलन की मदद से हल्का बेल लें। नान को ज्यादा पतला नहीं बेलना है, वरना ये फूलते समय सख्त हो सकता है।

बेलते समय आटे को समान मोटाई में रखें, ताकि ये तवे या ओवन में सही से पक सके। अब नान को गरम तवे पर या ओवन में सेकना शुरू करें। जैसे ही नान के ऊपर बुलबुले उठने लगें और हल्का सुनहरा रंग दिखाई दे, तब इसमें मक्खन लगाएं।

मक्खन से नान और अधिक स्वादिष्ट और मुलायम हो जाता है। अंत में बटर नान को गरम–गरम परोसें।

कहीं आपका बच्चा भी तो नहीं है खतरे में? ये छोटी सी लापरवाही हजारों बीमारियों का बन सकती है कारण

मोटापा, वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है, लगभग हर उम्र के लोग इस समस्या के शिकार हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मोटापा के कारण शरीर में कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। हृदय रोग, डायबिटीज से लेकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्याओं तक के लिए मोटापे को प्रमुख कारण माना जाता रहा है। जिस गति से बच्चों में यह समस्या बढ़ रही है वह अधिक चिंताजनक है।

बच्चों में अधिक वजन की स्थिति उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रभावित करती है। यह समय से पहले तमाम प्रकार की बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाली हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मोटापे के बढ़ते जोखिमों को लेकर लोगों को अलर्ट करता रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा न दिया गया तो बढ़ते मोटापे की समस्या गंभीर चिंता का कारण बन सकती है। बच्चों में यह समस्या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि इसके कारण कम उम्र में ही कई अन्य बीमारियों के विकसित होने का खतरा हो सकता है।

बच्चों में बढ़ते मोटापे की समस्या

बच्चों में मोटापे की स्थिति को लेकर साल 2022 में यूनिसेफ के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें शोधकर्ताओं ने चिंता जताई है कि जिस गति से बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं, अगर यही जारी रहा तो इस दशक के आखिर तक हर दस में से एक बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है। इस अनुमान के अनुसार 2.7 करोड़ से अधिक बच्चों में मोटापे का जोखिम हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जीवनशैली की निष्क्रियता और आहार की गड़बड़ी के कारण यह जोखिम काफी बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने भविष्य में मोटापे की महामारी को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया है।

मोटापा बढ़ने का कारण

यूनिसेफ शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि जीवनशैली की खराब आदतें, आहार में प्रोसेस्ड–जंक फूड्स को शामिल करना, मोबाइल गेम्स की बढ़ती आदतें और नींद के समय में आए बदलाव के कारण बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट (2019–20) के अनुसार भारत में 24 फीसदी महिलाएं और 23 फीसदी पुरुष मोटापे के शिकार थे। आनुवांशिक रूप से यह खतरा बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है।

शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने पर देना होगा जोर

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सेंडेंटरी लाइफस्टाइल का जोखिम अमूमन सभी आयुवर्ग वालों में देखा जा रहा है। बच्चे भी इसके शिकार हैं। भविष्य में मोटापे के कारण बढ़ने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम सभी अपने जीवनशैली को ठीक करें। दिनचर्या में एरोबिक अभ्यास को जरूर शामिल किया जाना चाहिए, ये सभी आयु वर्ग वालों के लिए जरूरी है। समय रहते अगर वजन को कंट्रोल न किया गया तो इसके कारण कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों के विकसित होने का जोखिम हो सकता है।

इन बीमारियों का जोखिम बढ़ा देता है मोटापा

बढ़ते वजन को हृदय रोगों से लेकर डायबिटीज, कैंसर और समय से पहले मौत के खतरे से जोड़कर देखा जाता है।

मोटापे के कारण बच्चों में भी ब्लड प्रेशर और कम उम्र में डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। समय से पहले इन बीमारियों के कारण जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर असर देखा जा सकता है। अगर समय रहते हमने स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ाने वाले उपाय नहीं किए तो यह हमारी सेहत के लिए कई प्रकार के जोखिमों का कारण बन सकता है।

फाइनेंस कंपनी से 7.37 लाख की जालसाजी, शाखा प्रबंधक व कैशियर पर प्राथमिकी

गोरखपुर, संवाददाता। क्षेत्र में संचालित एक फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी में 7.37 लाख रुपये की जालसाजी का मामला सामने आया है। कंपनी के शाखा प्रबंधक और कैशियर पर आपसी मिलीभगत से ग्राहकों की किस्तों की रकम हड़पने का आरोप है। दोनों आरोपी घटना के बाद से गायब हैं। मामले में एसपी नार्थ के निर्देश पर सहजनवां थाने में शाखा प्रबंधक मोहम्मद हुसैन और कैशियर राहुल राव के खिलाफ जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ई–केवाईसी के माध्यम से लोन उपलब्ध कराती है। ग्राहकों से लोन की राशि साप्ताहिक किस्तों में वसूली होती है। शाखा स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका सामने आई, जिसके बाद कंपनी ने आंतरिक ऑडिट और जांच कराई। जांच में पर्दाफाश हुआ कि शाखा प्रबंधक फरेंदा के मधुकरपुर निवासी शाखा प्रबंधक मोहम्मद हुसैन ने करीब 5.74 लाख रुपये की जालसाजी की है। इस पर कंपनी प्रबंधन ने जांच समिति गठित कर उसे पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि पूछताछ के दौरान वह दुकान से चाय पीने की बात कहकर बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा। तभी से वह गायब है।

जांच आगे बढ़ने पर कैशियर कुशीनगर के पुरैना रहसु पट्टी निवासी राहुल राव भी संदेह के घेरे में आ गया। ऑडिट में सामने आया कि कैशियर ने ग्राहकों की किस्तों से 1.62 लाख रुपये का गबन किया है। आरोप है कि दोनों कर्मचारी ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए उनकी बैंक पासबुक अपने पास रख लेते थे और यह कहकर किस्त स्वयं भरने का आश्वासन देते थे। इसी बहाने वसूली गई रकम कंपनी के खाते में जमा न कर निजी तौर पर हड़प ली गई। मामला संज्ञान में आन के बाद फाइनेंशियल लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर रोहित कुमार ने पूरे मामले की शिकायत एसपी नार्थ से की। एसपी नार्थ के आदेश पर सहजनवां पुलिस ने शाखा प्रबंधक और कैशियर के खिलाफ जालसाजी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र का कहना है कि दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। कंपनी के रिकॉर्ड, ग्राहकों की पासबुक और लेन–देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

एनसीसी अकादमी के नवनिर्मित भवन संग विरासत गलियारा का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी

गोरखपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। वह ताल कंदला स्थित एनसीसी के निर्माणाधीन अकादमी भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वह ट्रांसपोर्टनगर रैन बसेरा और विरासत गलियारा का भी निरीक्षण कर सकते हैं। जानकारी के मुबाबिक, मुख्य मंत्री रविवार को अपराह्न तीन बजे आएंगे और सीधे एनसीसी के निर्माणा धीन अकादमी भवन को देखने जाएंगे। मौके पर ही निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जानेंगे। इसके बाद वह ट्रांसपोर्टनगर रैन बसेरा और फिर विरासत गलियारा का निरीक्षण करने जा सकते हैं। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुबह जनता दर्शन करेंगे। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में अपराह्न तीन बजे विधायक खेल स्पर्धा समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके जरूरी निर्देश दिए।

संक्षिप्त खबरें

अब यूपी एक इस जिले में बंद हुए आठवीं तक के स्कूल

वाराणसी, संवाददाता। भीषण सर्दी और कोहरे को देखते हुए वाराणसी में कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल 29 और 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। यह आदेश बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने जारी किया है। बीएसए ने बताया कि आदेश का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। यूपी बोर्ड के साथ ही सीबीएसई और सीआईएससीई के स्कूल भी बंद रहेंगे। आदेश की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अगले तीन दिन रहेगी गलन

प्रदेश में हो रही भीषण ठंड लोगों की कंपकंपी छुड़ा रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले तीन दिनों तक इस गलन और कोहरे से राहत की संभावना नहीं है।

57 दिनों में चांदी ने 99 हजार की लगाई छलांग

वाराणसी, संवाददाता। एक साल में सोना दोगुना तो चांदी ने ढाई गुना की छलांग लगाई है। कीमतों में बढ़ोतरी के कारण महिलाओं का रुझान आभूषणों के लिए चांदी की ओर अधिक देखने को मिल रहा है, जबकि पुरुष वर्ग निवेश के नजरिये से चांदी को बेहतर विकल्प मान रहा है। सराफा एसोसिएशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष की शुरुआत यानी 1 जनवरी को सोने का भाव 78,800 रुपये प्रति दस ग्राम था। साल भर में इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई और 27 दिसंबर तक यह बढ़कर 143700 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया। इस तरह से सोने ने एक साल में लगभग 82.3 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस उछाल के कारण सोना जहां पारंपरिक निवेश और सुरक्षित विकल्प के रूप में अपनी पकड़ बनाए हुए है, वहीं आम ग्राहकों के लिए इसकी खरीदारी अब पहले की तुलना में महंगी हो गई है। दूसरी ओर चांदी ने इस साल निवेशकों को कहीं अधिक आकर्षित किया है। वर्ष की शुरुआत में चांदी का भाव 98,900 रुपये प्रति किलोग्राम था जो 27 दिसंबर को बढ़कर 2,52,735 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। इस तरह चांदी ने लगभग 155.6 प्रतिशत का रिटर्न देकर सोने से आगे निकलते हुए बाजार में नई पहचान बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक मांग और निवेश की बढ़ती रुचि ने चांदी की कीमतों को मजबूती दी है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के महामंत्री किशोर सेठ ने बताया कि वर्ष समाप्त होने में अभी करीब पांच दिन शेष हैं। इस दौरान कीमतों में और उतार–चढ़ाव संभव है। मौजूदा रुझान को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के आखिरी दिनों में भी कीमती धातुओं के भाव ऊंचे बने रह सकते हैं।

लग्न के लिए लोग कर रहे खरीदारी

उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ के अनुसार, इस समय लग्न का ऑफ–सीजन चल रहा है। इसकेचलते बाजार में भावों में हल्का घटाव–बढ़ाव बना रहता है। इसके बावजूद लोग अगले वर्ष के विवाह लग्न को ध्यान में रखते हुए अभी से खरीदारी कर रहे हैं।

एम्स में देर रात मरीजों को किया जा रहा शिफ्ट, गार्डों की भूमिका पर उठे सवाल

गोरखपुर, संवाददाता। एम्स में तैनात गार्डों पर मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने का आरोप लगा है। आरोप है कि इमरजेंसी के पास तैनात गार्ड निजी अस्पतालों की एंबुलेंस परिसर के अंदर बुलवाकर मरीजों को बाहर भिजवा रहे हैं। ये काम देर रात में किया जा रहा है। उध ार, एम्स प्रशासन ने आरोपों की जांच कराने की बात कही है। कुशीनगर के लक्ष्मीनारायण सिंह ने इसे प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक, एम्स के एक चिकित्सक उनके मरीज को निजी अस्पताल ले जाने के लिए एक निजी एंबुलेंस वाले का नंबर दिया था। 25 दिसंबर की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि रात में कुछ मरीजों को इमरजेंसी के बाहर से निजी अस्पतालों में भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शी की मानें तो इस दौरान एक गार्ड भी मौके पर मौजूद था। दावा किया कि अगर शाम से रात तक के बीच की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। लक्ष्मीनारायण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सख्ती के बाद अब एंबुलेंस चालकों के माध यम से मरीजों को बहलाकर निजी अस्पताल ले जाने का खेल एम्स में भी शुरू होने लगा है।

मामले को लेकर एम्स प्रशासन गंभीर

एम्स परिसर और इमरजेंसी के सामने निजी अस्पतालों की एंबुलेंस खड़ी रहती हैं। कई बार आईपीडी (इनपेशेंट डिपार्टमेंट) से भी मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने के मामले सामने आ चुके हैं। अब गार्ड की ही मिलीभगत की शिकायत से एम्स प्रबंधन गंभीर हो गया है। प्रबंधन के सूत्रों की मानें तो सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हो गई है।

व्हीलचेयर के लिए भी किल्लत

इमरजेंसी पहुंचे मरीज के परिजन ने जिम्मेदारों से व्हीलचेयर मांगी तो गार्ड ने पहले नर्स से पर्चा बनवाने की शर्त रख दी। आरोप है कि गार्ड लगातार कहते हैं, यहां अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। उसी रात देवरिया से आए एक अन्य मरीज को भी निजी अस्पताल भेजा गया, जिसके साथ एक गार्ड गेट तक गया। एम्स में मरीजों के बेहतर उपचार के लिए प्रबंधन का प्रयास रहता है। नई फैकल्टी और कुछ नई नियुक्तियां भी कराई जाएंगी, जिससे उपचार में और सहूलियत मिलेगी। आरोपों की जांच कराई जा रही है। बार–बार आरोप लगने से छवि खराब होती है

एनईआर में 67 ट्रेनों की टाइमिंग बदली, गोरखपुर की 16 ट्रेनें शामिल– 1 जनवरी से होगा बदलाव

गोरखपुर, संवाददाता। रेलवे ने एक जनवरी से ट्रेनों की समय–सारिणी में बदलाव किया है। पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) की 67 ट्रेनों के प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। अब इन ट्रेनों की यात्रा प्रारंभ होने की समय–सारिणी निर्धारित समय से तीन से 10 मिनट पहले कर दी गई है। इनमें अधिकांश ट्रेनें दक्षिण भारत, दिल्ली, बिहार और कोलकाता की ओर जाने वाली हैं।

नए शेड्यूल के अनुसार, गोरखपुर से गुजरने वाली बिहार और दिल्ली रूट की 27 ट्रेनें, गोरखपुर से प्रारंभ होकर जाने वाली 16 ट्रेनें, वाराणसी मंडल की 24 ट्रेनें और इज्जतनगर मंडल की 40 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

गोरखपुर से बनकर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में गोरखपुर–यशवंतपुर राप्तीसागर एक्सप्रेस, गोरखपुर–कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, गोरखपुर–सिवान, गोरखपुर–थावे, गोरखपुर–छपरा, गोंडा–एलटीटी, सीतापुर–मैलानी समेत कुल 16 ट्रेनें शामिल हैं।

इसी तरह गोरखपुर से होकर गुजरने वाली 27 ट्रेनों की समय–सारिणी में भी बदलाव किया गया है। इनमें अमृतसर–सहरसा, ग्वालियर–बरौनी, गोंडा–छपरा, दिल्ली–सीतामढ़ी, आनंद विहार–मुजफ्फरपुर, दिल्ली–किशनगंज, लखनऊ–पटना, आनंद विहार–रक्सौल, आनंद विहार–बापूधाम मोतिहारी, अमृतसर–न्यू जलपाईगुड़ी, उदयपुर–न्यू जलपाईगुड़ी सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।

एनईआर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को समय परिवर्तन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि एक जनवरी से बदली हुई समय–सारिणी के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

संक्षिप्त खबरें

मारपीट का विरोध करने पर चार पहिया वाहन से कुचला, तीन घा यल

प्रयागराज, संवाददाता। यमुनापार इलाके में औद्योगिक थाना क्षेत्र के रामपुर में मारपीट का विरोध करने पर लोगों को चार पहिया वाहन से कुचलने का मामला सामने आया है। वारदात में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। आरोप है कि घटना की लिखित शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। औद्योगिक थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी अमित कुमार शनिवार की रात घर के समीप एक किराने की दुकान से सामान खरीदने गया था। इस दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे अपने पास बुलाया। वह सामान खरीद रहा था, इसलिए उसे मौके पर जाने में देर हो गई, जिससे वह गुस्सा हो गया और उसने अमित की पिटाई कर दी। अमित ने घर पहुंचकर यह बात अपने परिजनों को बताई। परिवार के लोग जब आरोपी के घर उलाहना देने पहुंचे तो आरोपी उसी समय पहुंच गया और उसने चार पहिया वाहन से सभी को कुचल दिया। वारदात में अमित कुमार, शिव लोचन और कौंधि यारा थाना क्षेत्र के चितौरा निवासी सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोग थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले की लिखापढ़ी नहीं की गई। उन्हें टरका दिया गया। जिससे आक्रोश और बढ़ गया और लोगों ने थाने का घेराव किया। घटना में घायल लोगों को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बनारस स्टेशन पर कार पार्किंग का किराया नहीं लगेगा

वाराणसी, संवाददाता। बनारस रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार पर दोपहिया साइकिल स्टैंड बंद होने के बाद अब यहां चल रही कार व ऑटो की पार्किंग (स्टैंड) भी बंद हो गई है। स्टैंड के प्रवेश द्वार पर ही पार्किंग का अनुबंध निरस्त होने की सूचना वाला बोर्ड लगाया गया है। ऐसे में लोग बिना किसी शुल्क के अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। बनारस स्टेशन से हर दिन 100 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बाहर निकलने के बाद दूसरे प्रवेश द्वार के पास पहले दोपहिया साइकिल स्टैंड चलता था। घाटा बताकर उसे इसी महीने में बंद कर दिया गया। इधर शनिवार को कार पार्किंग भी बंद कर दी गई है। यहां जो बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है कि पार्किंग का अनुबंध ा निरस्त किया जा चुका है, ऐसे में पार्किंग का कोई पैसा नहीं लगेगा। हालांकि तीन दिन पहले तक यहां दूसरे प्रवेश द्वार से जैसे ही कोई कार अंदर आती थी, उसे देखते ही पार्किंग संचालन से जुड़े युवक तुरंत कार के पास पहुंच जाते थे और पैसा लेकर ही कार को आगे जाने देते थे। जबकि पार्किंग के गेट पर ही लिखा था कि पिक एंड ड्रॉप का कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद भी युवक बिना कार चालक को पर्ची पकड़ो आगे नहीं जाने देते थे। अब पार्किंग बंद हो गई है।

बनारस पर एक और वाराणसी सिटी स्टेशन पर बिछेंगी 2 अतिरिक्त लाइनें

रेलवे की ओर से वाराणसी सहित कई शहरों में ट्रेनों के संचालन विस्तार की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसमें बनारस स्टेशन पर एक रेल लाइन बढ़ाई जाएगी।

अनुकंपा नौकरी के लिए 12 साल बाद हाईकोर्ट पहुंचा युवक, याचिका खारिज, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

प्रयागराज, संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुराने सेवा विवाद में दाखिल की गई समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 4,430 दिन (करीब 12 साल) की देरी से दाखिल याचिका के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने सहारनपुर निवासी की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामला सहारनपुर जिले के मूल निवासी मुल्की राज से जुड़ा है। मुल्की राज ने साल 1996 में हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा से जुड़े विवाद को चुनौती दी थी। इस मामले में उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम राहत भी मिली। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिट याचिका को 10 सितंबर 2013 को पूरी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद मुल्की राज ने न तो इस आदेश के खिलाफ कोई अपील की और न ही समीक्षा याचिका दाखिल की। मुल्की राज साल 2018 तक सेवा में

रहे। 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके बेटे ने हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की कि वर्ष 2013 का कोर्ट आदेश उनकी अनुकंपा नियुक्ति (सरकारी नौकरी) के रास्ते में बाधा बन रहा है। हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इतने लंबे समय बाद समीक्षा याचिका दाखिल करने का आधार अनुकंपा नौकरी नहीं हो सकती। वहीं, कोर्ट ने कहा कि मूल याचिकाकर्ता ने अपने जीवनकाल में फैसले को चुनौती नहीं दी तो उसके बेटे को इस मामले में समीक्षा याचिका दाखिल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने देरी माफी आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि 4,430 दिन की देरी को लेकर याचिका में दिए गए कारण अस्पष्ट और कमजोर हैं। देरी माफी आवेदन खारिज होने के साथ ही समीक्षा याचिका भी स्वतः खारिज हो गई। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सहारनपुर में जमा करने का आदेश दिया।

लाइव वीडियो में सल्फास पीकर युवक बोला, पहले नौकरी से निकाला

प्रयागराज, संवाददाता। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के सुरक्षा गार्ड रहे विपिन शुक्ल ने 17 दिसंबर को जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने नौकरी के नाम पर कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कहा कि पहले नौकरी से निकाल दिया और अब दोबारा रखने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। नवाबगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि, अमर उजाला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 13 मिनट 48 सेकेंड के वीडियो में विपिन कहता है कि मैं सल्फास खाकर सुसाइड करने जा रहा हूं। आरोप लगाया कि उसकी मौत का जिम्मेदार संस्थान के कुछ लोग है। कहा कि, उसने 12 साल नौकरी की, लेकिन पिछले छह महीने से मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। एक लोग के द्वारा युवतियों से छेड़खानी की जा रही थी, इसकी शिकायत की तो उसे कंपनी से निकाल दिया गया। बाद में नौकरी लगवाने के एवज में रुपये मांगा जाने लगा। कर्ज लेकर पहले 30 हजार, 20 हजार और 20 और फिर 50 हजार रुपये दिए। घर का अकेला कमाने वाला हूं। बहन की शादी में पांच–छह लाख का कर्ज हो गया। हिम्मत टूट गई है। हालात बहुत खराब है।

आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने एफिडेविट बनवाकर जमा करने को कहा है, लेकिन इसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। नौकरी के लिए मुझे मेरठ भेजा गया। एक लोग का नाम लेते हुए कहा कि उसने बोला उसे कुछ नहीं पता और ज्वाइन करने के लिए एक और लोग से बात करने को कहा गया।

इकलौते बेटे की मौत है, आरोपियों पर कार्रवाई हो...

नवाबगंज के कस्तूरीपुर हुलासी का पूरा निवासी अंजली ने पुलिस को बताया कि 17 दिसंबर की शाम विपिन ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, मृत्यु के समय विपिन का मोबाइल लॉक था। बाद में फोन खुलवाने पर उसमें एक लाइव वीडियो मिला। पिता रामकैलाश शुक्ला ने बताया कि विपिन घर का इकलौता बेटा था। वह एमएनएनआईटी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसने अपनी जान गवां दी। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। वहीं, नवाबगंज थाना प्रभारी का कहना है कि प्रारंभिक जांच कर साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। घटना की पुष्टि के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

माघ मेला में कल्पवासियों के आगमन के लिए यातायात रूट तय, हर जिले के लिए अलग रूट निर्धारित

प्रयागराज, संवाददाता। आगामी तीन जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से माघ मेला–2026 की शुरुआत हो रही है। कल्पवासियों के सुगम व सुरक्षित आवागमन के लिए मेला पुलिस ने यातायात रूट तय कर दिया है। लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर समेत अन्य मार्गों से आने वाले कल्पवासियों की सुविधा को देखते हुए मेला पुलिस ने आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि यह व्यवस्था कल्पवासियों के लिए लागू कर दी गई है। जौनपुर मार्ग– जौनपुर मार्ग से आने वाले सभी कल्पवासी अपने वाहन के साथ सहसों–अंदावा मार्ग पर रहिमापुर तिराहे से दाहिने मुड़कर एजे मार्ग, ओल्ड जीटी मार्ग से लोअर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।

वाराणसी मार्ग– वाराणसी मार्ग से आने वाले सभी कल्पवासी अपने वाहन के साथ अंदावा तिराहा, कटका तिराहा से दाहिने मुड़कर ओल्ड जीटीमार्ग से लोअर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।

मिर्जापुर/चित्रकूट–रीवां मार्ग– मिर्जापुरधचित्रकूट–रीवां मार्ग से आने वाले कल्पवासी अपने वाहन के साथ लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर, शास्त्री पुल, कटका तिराहा से बाएं मुड़कर ओल्ड जीटी मार्ग से लोअर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।

कानपुर–प्रयागराज– कानपुर से प्रयागराज शहर क्षेत्र में आने वाले कल्पवासी अपने हल्के वाहन के साथ जीटी जवाहर चौराहा से ओल्ड जीटी मार्ग थाना दारागंज के सामने से होते हुए पांटून पुल नंबर पांच से झूंसी क्षेत्र में लोअर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। लखनऊ–अयोध्या–प्रतापगढ़ मार्ग– लखनऊ–अयोध्या–प्रतापगढ़ मार्ग से आने वाले कल्पवासी अपने वाहन के साथ बसना नाला पुल पारकर पुराना फाफामऊ बाजार, थरवई–सहसों–अंदावा मार्ग पर रहिमापुर तिराहे से दाहिने मुड़कर एजे मार्ग के रास्ते ओल्ड जीटी मार्ग होकर लोअर संगम मार्ग से कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। लखनऊ–अयोध्या–प्रतापगढ़ मार्ग से आने वाले समस्त कल्पवासी अपने हल्के वाहन के साथ चंद्रशेखर आजाद पुल को पारकर बाएं (मेंहदौरी पुलिस चौकी) रिवरफ्रंट मार्ग से बाएं मुड़कर पांटून पुल से लोअर संगम मार्ग के रास्ते कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।

लखनऊ–अयोध्या–प्रतापगढ़– मार्ग से कल्पवासी अपने वाहन के साथ चंद्रशेखर आजाद पुल होते हुए एमएनएनआईटी तिराहा, मजार तिराहा से बाएं मुड़कर आईईआरटी फ्लाईओवर से रिवर फ्रंट मार्ग ये बांए मुड़कर पांटू पुल नं0–05 से झूंसी क्षेत्र के लोअर संगम मार्ग से कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। कल्पवासी माघ मेला सेक्टर सात में रहकर कल्पवास करना चाहते हैं वह लेप्रोसी चौराहा तक पहुंचकर नव प्रयागम अप्रोच मार्ग, अरैल बांध मार्ग से सोमेश्वर महादेव रैंप व महाकाल रैंप से नीचे उतरने के बाद कैंप तक जा सकेंगे।

ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने फार्च्यूनर से 700 मीटर तक छात्र की बाइक को घसीटा

वाराणसी, संवाददाता। कैंट थाना क्षेत्र के अर्दली बाजार में शनिवार शाम फॉर्च्यूनर सवार ने यूपी कॉलेज के छात्र की बाइक में टक्कर मार दी। फॉर्च्यूनर सवार बाइक को घसीटते हुए 700 मीटर दूर तक अर्दली बाजार चौकी तक ले गया। यूपी कॉलेज के छात्रों और राहगीरों ने पथराव कर शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। किसी तरह कैंट पुलिस ने फॉर्च्यूनर चालक को बचाया। फॉर्च्यूनर सवार युवक चंदौली के धानापुर ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह खलनायक का बेटा है। गाड़ी अजय की पत्नी मीरा सिंह के नाम पर आरटीओ में रजिस्टर्ड है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का चिन्हांकन शिविर 30 दिसंबर को - जिलाधिकारी

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल योजनान्तर्गत एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से सम्बन्धित चिन्हांकन शिविर का आयोजन 30 दिसम्बरको विकास खण्ड परिसर रुदौली अयोध्या में किया जायेगा।ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा अभी तक मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल योजना से लाभान्वित नहीं किया गया हो एवं उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 80 प्रतिशत हो वे दिव्यांग चिन्हांकन शिविर में उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन वांछित प्रपत्रों (आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता प्रदर्शित

फोटोग्राफ) के साथ उपस्थित होकर करा सकते है।शिविरों के सफलतापूर्ण आयोजन हेतु निम्न अधिकारियों को लगाया गया है।जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी सुशील कुमार को शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों के उपकरण हेतु आवेदनों पर सरकारी चिकित्सक की संस्तुति हेत शिविर स्थल पर चिकित्सकों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। उपजिलाधिकारी रुदौली को पत्र दिव्यांगजनों के आय, जाति, निवास आदि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।खण्ड विकास अधिकारी, रुदौली को शिविर स्थल पर दिव्यांगजनों के आनलाईन आवेदन कराये जाने हेतु 01 कम्प्यूटर आपरेटर (डेस्कटापध्लैपटाप सहित) का प्रबन्ध करना। शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों हेतु बैठने, ठंड से बचाव हेतु अलाव आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी को शिविर स्थल पर सहायक विकास अधिकारी (स०क०) के माध्यम से योजनाओं से वंचित दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर लाये जाने हेतु प्रेरित करने तथा शिविर के दिन उन्हें स्थल पर उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देश प्रदान करें।जिला कार्यकम अधिकारी अजय तिवारी अपने अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के माध्यम से योजनाओं से वंचित दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर लाये जाने हेतु निर्देश प्रदान करें।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि डीएम के निर्देश पर चिन्हांकन शिविर को सफल बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

डॉक्टर दंपती के जन्मजात विकृति वाले गर्भस्थ शिशु को बता दिया तंदुरुस्त

लखनऊ, संवाददाता। महानगर स्थित एक प्रतिष्ठित निजी डायग्नोस्टिक सेंटर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। केंद्र ने प्रसव पूर्व कराई जांच में डॉक्टर दंपती के बच्चे को स्वस्थ बता दिया, जबकि वह जन्मजात विकृतियों से जूझ रहा था। आठवें महीने में दूसरे केंद्र से जांच करवाने पर इसका पता चला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जन्म के चार महीने बाद बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित डॉक्टर दंपती ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और नेशनल मेडिकल काउंसिल से शिकायत की है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। राजाजीपुरम निवासी डॉ. मानवी सरकारी चिकित्सक हैं। गर्भावस्था के दौरान गोमतीनगर के कॉर्पोरेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने पिछले वर्ष महानगर के निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से कलर डॉप्लर, ईको और टिफा जैसी अहम जांचें करवाईं। निजी केंद्र ने अपनी सभी रिपोर्टों में गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ बताया। गर्भावस्था के आठवें महीने में डॉ. मानवी ने दूसरे केंद्र से अल्ट्रासाउंड कराया तो गर्भस्थ शिशु में कई विकृतियों का पता चला। दोबारा जांच कराने पर भी इसकी पुष्टि हुई कि बच्चे के अंगों में खामियां हैं। पांच अगस्त को जन्मे बच्चे का एक हार्ट वॉल्व नहीं था। इसके अलावा कई अंग पूरी तरह विकसित नहीं थे। 15 दिसंबर को बच्चे ने दम तोड़ दिया। पिता डॉ. अनिल ने डिप्टी सीएम व एनएमसी से लिखित शिकायत की है। सीएमओ ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है।

संक्षिप्त खबरें

अभी भी जिले के कई थानों पर पुलिस चौकियों पर अंगद की तरह पैर जमाए सिपाही

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जिले के कई थानों तथा चौकियों पर 3 वर्ष पूरे होने के बाद कुछ सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया था।लेकिन आज भी अंगद की तरह तबादले के बाद भी पैर जमाए कोतवाली छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ,एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के द्वारा एक ही थाने व कोतवाली व चौकी में तैनात 3 वर्षों से सिपाहियों का बड़े पैमाने पर स्थानंतरण किया गया था कुछ सिपाही ने उसका पालन करते हुए संबंधित थाना और कोतवाली जाकर चार्ज ले लिया लेकिन कुछ सिपाही स्थानांतरण होने के बाद भी बीकापुर सहित कई थानों तथा पुलिस चौकियों पर अंगद की तरह पैर जमाए कार्य कर रहे हैं।चर्चा है कि सीओ और प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष ऐसे सिपाहियों पर मेहरबान है जिसके चलते स्थानांतरण के बाद भी सिपाही का जमा होना चर्चा का विषय बना हुआ है जबकि इसके बारे में कई महीने पूर्व एक संस्था व दल के द्वारा लिखा पढी भी की गई थी। लेकिन उसे कार्रवाई से स्थानांतरण सिपाहियों में थोड़ी सी हलचल मच गई थी उसके बाद शांत हो गया। चर्चा है कि क्षेत्र के बारे में जो सिपाही ज्यादा जानकारी रखता है आने वाले कोतवाल जल्दी उसे छोड़ना नहीं चाहते जिसके चलते 3 वर्ष ट्रांसफर होने के बाद संबंधित थाने में जमे है।

एसपी सिटी व एसपी ग्रामीण सहित सभी सीओ ने साथ चलाया चेकिंग अभियान

अयोध्या। नये वर्ष के आगमन व घने कोहरे को लेकर जिले मे पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों मे पैदल गस्त कर रहे है।सोमवार को एसएसपी डॉक्टर डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी तथा एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी की देखरेख में सभी सीओ अपने अपने क्षेत्र में संबंधित प्रभारी निरीक्षकों ध्थानाध्यक्ष के साथ पैदल गस्त कर लोगों को सुरक्षा के प्रति एहसास कराया।इन पुलिस अधिकारियो ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान चलाने वालों मे एसपी ग्रामीण व एसपी सिटीके अलावा सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी, को अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी, सीओ सदर अरविंद सोनकर, कॉप बीकापुर पीयूष,सीओ मिल्कीपुर राकेश कुमार, सीओ रुदौली आशीष निगम के अलावा महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला शामिल रही।पुलिस अधिकारियों ने खासकर हाईवे पर आने जाने वाले भारी वाहनों जिसमें ट्रैक्टर ट्राली ट्रक डीसीएम के अलावा ऐसे वाहन जिस पर रिफ्लेक्टर तथा फोग लाइट नहीं लगी हुई थी उन्हें चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि आने वाले दिनों में शीत लहरी तथा कोहरे को देखते हुए सभी लोग इसका प्रयोग करें क्योंकि अधिकतर दुर्घटना से गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहनों तथा सामने से आ रहे वाहनों की दिखाई ना पडने के चलते हो रही है।इसके अलावा इन पुलिस अधिकारियों ने पैदल ग्रस्त करते हुए स्थानीय लोगों से अपील किया कि वे सभी संदिग्ध रूप में दिखाई देने वाले लोगों के बारे में बेहिचक स्थानीय पुलिस थानों तथा पुलिस चौकिया पर जाकर कह सकते हैं जिससे कि समय रहते किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके।वही नव वर्ष को देखते हुए इन पुलिस अधिकारियों ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी किया।

अभाविप, काशी प्रांत के प्रांतीय अधिवेशन का जौनपुर में हुआ शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी प्रांत के 65वें प्रांतीय अधिवेशन का भव्य शुभारंभ सोमवार को जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अस्थाई रूप से बसाए गए श्रानी अब्बक्का नगरश के श्महंत अवैद्यनाथ सभागारश में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रख्यात भारतीय कुश्ती खिलाड़ी पद्मश्री योगेश्वर दत्त एवं विशेष रूप से उपस्थित अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान मंच पर अतिथियों के साथ नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष डॉ महेंद्र त्रिपाठी, नवनिर्वाचित प्रांत मंत्री शिवम सिंह, स्वागत समिति अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश एवं स्वागत समिति मंत्री पुष्पराज सिंह उपस्थित रहे। अधिवेशन का शुभारंभ सोमवार सुबह संगठन के ध्वज के ६ वजारोहण और सामूहिक वंदे मातरम् के साथ हुआ। अभाविप, काशी प्रांत के निवर्तमान प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह ने विगत वर्ष का वृत्त प्रस्तुत करते हुए यह आंकड़ा रखा कि अभाविप, काशी प्रांत ने इस वर्ष सदस्यता के सभी पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ 3,86,091 विद्यार्थियों की सदस्यता की है। अभाविप, काशी प्रांत की संगठनात्मक यात्रा में यह संख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात, प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी डॉ अखिलेश पाण्डेय ने काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष तथा प्रांत मंत्री की घोषणा की। चुनाव प्रकिया में जौनपुर निवासी डॉ महेंद्र त्रिपाठी को अभाविप, काशी प्रांत अध्यक्ष एवं भदोही के शिवम सिंह को अभाविप, प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त सीटें एवं देर तक चलती प्रवेश प्रक्रिया चिंतनीय, वंदे मातरम् के 150 वषर्रू राष्ट्र चेतना का अमर घोष, स्क्रीन टाइम से ग्रीन टाइम की ओररू एक संतुलित जीवन की पहल, सीमांत से सशक्तिकरण तकरू सोनभद्र के उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना विषयक चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव को इस अधिवेशन के प्रथम दिवस पर प्रस्तुत किया गया है। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश ने कहा कि,६ वर्तमान समय में भारतवर्ष को एक बार फिर राष्ट्रीय पुनरुत्थान की आवश्यकता है, जिसका आधार ज्ञान और चरित्र की शिक्षा होनी चाहिए। एकता में ही वास्तविक शक्ति है, जो शांति की स्थापना करती है। देश तभी सशक्त बनेगा जब हम श्व्यक्ति की जयश के स्थान पर श्भारत की जयश के संकल्प के साथ कार्य करेंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए जन–जन में परिवर्तन और मातृ–शक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। साथ ही, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को नशे के चंगुल से बचाएं और राष्ट्र के शत्रुओं व मित्रों की सही पहचान करें, ताकि हमारे अस्तित्व पर कोई संकट न आए।६ उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रख्यात भारतीय कुश्ती खिलाड़ी पद्मश्री योगेश्वर दत्त ने कहा कि,ष्अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सदैव अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। यह संगठन निरंतर देश को गढ़ने और उसे प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के विजन के साथ कार्य कर रहा है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उसके युवाओं में निहित होती है यदि युवा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो राष्ट्र स्वतः ही सशक्त बन जाता है। राष्ट्र निर्माण में समाज के हर वर्ग का योगदान अतुलनीय है, जहाँ खिलाड़ी वैश्विक पटल पर देश का मान बढ़ाते हैं और फौजी सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहीं शिक्षक भावी पीढ़ी को शिक्षित कर देश का आधार तैयार करते हैं। हमें यह समझना होगा कि निस्वार्थ भाव से की गई समाज सेवा भी वास्तव में देश सेवा ही है। हमारा लक्ष्य पूरे समाज को एकजुट कर साथ लेकर चलना होना चाहिए ताकि हम मिलकर भारत को उन्नति की नई ऊंचाइयों पर पहुँचा सकें। उद्घाटन सत्र में विशेष रूप से उपस्थित अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह ने कहा कि,ष्आज के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसे छात्र संगठन के रूप में कार्यरत है, जिसका मूल संकल्प केवल राष्ट्र सेवा है। वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी के सामने बढ़ता हुआ श्स्क्रीन टाइमश एक गंभीर चुनौती है, जो मानसिक अवसाद का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसके साथ ही, आज शैक्षणिक परिसरों में ऐसी विचारधाराओं की अधिकता दिखती है जो समाज को तोड़ने का प्रयास करती हैं, जबकि सकारात्मक रूप से जोड़ने वाले लोग कम हैं। अतः यह अनिवार्य है कि छात्र शक्ति जागरूक बने और विध्वंसक प्रवृत्तियों को त्यागकर एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे।६

संक्षिप्त खबरें

कठिन परिश्रम और अनुशासन से ही मिलती है सफलता : योगेश्वर दत्त

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, के एकलव्य स्टेडियम में सोमवार को खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी क्षण देखने को मिला, जब लंदन ओलंपिक 2012 के कांस्य पदक विजेता एवं देश के गौरव ओलंपियन योगेश्वर दत्त का आगमन हुआ। उनके आगमन से विश्वविद्यालय परिसर का खेल वातावरण उत्साह और ऊर्जा से भर उठा। एकलव्य स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने कहा कि सफलता का एकमात्र मार्ग कठिन परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी है। उन्होंने खिलाड़ियों से माता–पिता एवं कोच का सम्मान

करने का आह्वान करते हुए कहा कि जो खिलाड़ी संस्कारों और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है। उनके विचारों ने उपस्थित खिलाड़ियों के मन में आत्मविश्वास, संकल्प और नई ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर योगेश्वर दत्त का भव्य एवं आत्मीय स्वागत विश्वविद्यालय के खेल सचिव प्रो. शेखर सिंह, डॉ. रणधीर सिंह, डॉ. राजेश सिंह (जिला मंत्री, क्रीड़ा भारती), बाबा मौर्य (जिला अध्यक्ष, क्रीडा भारती), डॉ. रामधारी, पूर्व कर्मचारी संघ के महामंत्री रमेश यादव,अलका सिंह, अशोक सोनकर, योग प्रशिक्षक जय सिंह, भानु प्रताप शर्मा, सत्येंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह, परशुराम, संत राज, सिकंदर एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रही महिला क्रिकेट टीम, महिला योग टीम तथा कुश्ती के कई दर्जन खिलाड़ियों उपस्थिति रही। खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों ने ओलंपियन श्री दत्त को बुके, माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एबीवीपी अधिवेशन के विरोध में NSUI का शांतिपूर्ण प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी द्वारा कराए जा रहे तथाकथित अधिवेशन के विरोध में आज शहर ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव के अध्यक्ष अमन सिन्हा के नेतृत्व में अम्बेडकर तिराहा पर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के साथ लोकतांत्रिक एवं अहिंसात्मक तरीके से विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर को किसी भी प्रकार की राजनीतिक अराजकता, वैचारिक दमन और छात्र हितों के विरुद्ध गतिविधियों से बचाना है। शहर अध्यक्ष अमन सिन्हा ने कहा कि, "पूर्वांचल विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, न कि किसी संगठन की राजनीति का मंच। एबीवीपी द्वारा इस तरह के अधिवेशन कराकर छात्रों के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे NSUI कभी स्वीकार नहीं करेगी।

खुटहन थाना अंतर्गत पुलिस ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हत्याकांड का किया खुलासा दो गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में खुटहन थाना अंतर्गत बीते दिनों एक ग्राहक सेवा संचालक की हुई हत्या का सोमवार को अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक शहर आयुश श्रीवास्तव ने खुलासा करते हुए बताया कि चुनावी रंजिश में हुई फूलचंद की हत्या किया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों राजेश यादव और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। यह घटना 26 दिसंबर 2025 को हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपियों को वनुआडीह तिराहे से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया ईंट का टुकड़ा, मृतक के दुकान से एक स्क्रीन टच मोबाइल (जिसमें वोडाफोन सिम था) और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार आरोपी राजेश यादव ने पुलिस को बताया कि उसने वर्ष 2005 में प्रधानी का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गया था। वर्ष 2015 में सीट सुरक्षित होने पर मृतक फूलचंद ने चुनाव लड़ा था। राजेश यादव ने अपनी ओर से रामश्रृंगार पासवान को चुनाव लड़वाया था, जो जीत गए थे। तभी से फूलचंद उससे रंजिश रखते थे। राजेश को आशंका थी कि फूलचंद उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। राजेश यादव ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 की सुबह वह अंकित गुप्ता के साथ फूलचंद के जनसेवा केंद्र पर पहुंचा। उसने फूलचंद से इस बार चुनाव न लड़ने के लिए कहा। इसी दौरान दोनों के बीच बात बढ़ गई। आवेश में आकर राजेश ने दुकान के पास रखी ईंट उठाकर फूलचंद पर वार कर दिया। अंकित गुप्ता ने भी राजेश का साथ

दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने दुकान का शटर बंद कर दिया और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। उन्होंने फूलचंद का मोबाइल एनएनसी स्कूल के अहाते में फेंक दिया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस और फूलचंद के परिवार की हर गतिविधि। पर नजर रखी, ताकि किसी को उन पर शक न हो, लेकिन वे पुलिस की नजरों से बच नहीं पाए और पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजेश यादव पुत्र स्व० पारस यादव, निवासी ग्राम पनौली, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर (59) और अंकित गुप्ता पुत्र संतोष गुप्ता, निवासी ग्राम पनौली, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर (18) के रूप में हुई है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर

लखनऊ, संवाददाता। उप्र पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्टूबर माह के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2026 में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 2.33 प्रतिशत का रिबेट मिलेगा। इससे जनवरी माह में बिजली दरें एक माह के लिए सस्ती रहेंगी और प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। इससे पहले सितंबर माह का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं को करीब 264 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास जमा है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 18,592 करोड़ रुपये का सरप्लस और जुड़ने की संभावना है। इस प्रकार प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस बिजली कंपनियों पर बना हुआ है। उन्होंने मांग की कि जब तक उपभोक्ताओं का यह सरप्लस उपलब्ध है, तब तक ईंधन अधिभार शुल्क के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली न की जाए, बल्कि आवश्यक समायोजन सरप्लस से ही किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू हो चुका है तथा प्रदेश में नई बिजली दरों के आदेश भी प्रभावी हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में भी ईंधन अधिभार शुल्क में कमी जारी रहने की पूरी संभावना है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे हस्तक्षेप करें, जिससे प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में बड़े पैमाने पर हो रही संविदा कर्मियों की छंटनी और रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हजारों पदों को समाप्त करने का सिलसिला बंद हो। उन्होंने कहा कि छंटनी से प्रदेश की बिजली व्यवस्था के पटरी से उतरने का खतरा है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे मुख्य मकसद प्रदेश के कई शहरों की बिजली व्यवस्था फ्रेंचाइजी को देना है जबकि आगरा में फ्रेंचाइजी का प्रयोग पूरी तरह विफल हो चुका है। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को विगत मई माह से हजारों की संख्या में बिना किसी मापदंड के हटाया जा चुका है। मई 2017 में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा जारी आदेश में संविदा कर्मियों को रखे जाने के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इनके अनुसार शहरी क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र पर 36 कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्र पर 20 कर्मचारी होने चाहिए।

समिति ने बताया कि सभी विद्युत वितरण निगमों में संविदा कर्मियों के किए जा रहे नए टेंडर में मई, 2017 के मापदंड का उल्लंघन करते हुए 27% से 45% तक संविदा कर्मियों की छंटनी की जा रही है। संघर्ष समिति ने कहा कि इसके साथ ही लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, नोएडा में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर हजारों नियमित पदों को समाप्त कर दिया गया है।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आयोजित प्रांत अधिवेशन में पदाधिकारियों का निर्वाचन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के तीन दिवसीय सम्मेलन के प्रथम दिन काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष तथा प्रांत मंत्री के दायित्वों की निर्वाचन प्रक्रिया आज हुई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अस्थाई रूप से बसाए गए श्रानी अब्बक्का नगरश के श्महंत अवैद्यनाथ सभागारश में संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी प्रांत के प्रांत अध्यक्ष के रूप में डॉ. महेंद्र त्रिपाठी का निर्वाचन हुआ है तथा प्रांत मंत्री के दायित्व पर शिवम सिंह निर्वाचित हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी प्रांत का 65वाँ प्रांत अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर के मध्य संपन्न होगा, जिसमें काशी प्रांत के कुल 18 सांगठनिक जिलों से लगभग 850 कार्यकर्ता अधिवेशन में प्रतिभाग कर रहे हैं। अधिवेशन के प्रथम दिवस पर चुनाव अधिकारी डॉ अखिलेश पाण्डेय ने प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें क्रमशः महेंद्र त्रिपाठी एवं शिवम सिंह को प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। नवनिर्वाचित काशी प्रांत अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी मूलतः जौनपुर के निवासी हैं।

आपकी शिक्षा टी.डी. कॉलेज, जौनपुर से एम.ए. एवं शोध कार्य तक पूर्ण हुई है। पूर्व में आपने नगर अध्यक्ष, जिला प्रमुख (हरदोई), विभाग प्रमुख (हरदोई) तथा काशी प्रांत उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण सांगठनिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी प्रांत से आपका संपर्क वर्ष 2012 से है। वर्तमान में अभाविप काशी प्रांत के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार नवनिर्वाचित काशी प्रांत शिवम सिंह मूलतः भदोही के निवासी हैं। इनकी शिक्षा स्नातक एवं परास्नातक रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई है। पूर्व में इकाई कार्यकारिणी सदस्य, इकाई उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, प्रांत कार्यसमिति सदस्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जैसे महत्त्वपूर्ण दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क वर्ष 2016 से है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।